

पूँजीपति वर्ग की नजर में मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग

दि ल्ली में बलात्कार की घटना के विरोध में मध्यमवर्गीय छात्रों-नौजवानों ने सराहनीय सक्रियता का परिचय दिया। इस मामले में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालय के छात्रों और वहां छात्र संघ ने पहलकदमी ली। उनके विरोध प्रदर्शन की प्रेरणा से दिल्ली के अन्य मध्यमवर्गीय रिहायशी इलाकों में विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए। फिर इन्हीं छात्रों ने 22 दिसम्बर को इंडिया गेट पर प्रदर्शन का आह्वान किया। यहां बड़ी संख्या में छात्र-नौजवान तथा अन्य मध्यमवर्गीय लोग इकट्ठा हुए। उस दिन तथा अगले दिन पुलिस ने बल प्रयोग किया। 23 दिसम्बर की शाम को पर्याप्त बल प्रयोग कर पुलिस ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच पूरा मैदान खाली करा लिया। पिछले साल अन्ना-केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ही यह दिख रहा है कि मध्यम वर्ग, खासकर इसका छात्र-युवा हिस्सा कुछ खास मुद्दों पर सक्रियता दिखा रहा है। ये मुद्दे विशेष तौर पर मध्यम वर्ग से जुड़े होते हैं। अक्सर ही इसमें अपराध का कोई-न-कोई हिस्सा होता है तथा मध्यम वर्ग को संबोधित समाचार चैनल उस मुद्दे को उछाल रहे होते हैं।

वस्तुतः ये चैनल ही उस मुद्दे पर मध्यमवर्गीय सक्रियता के सबसे बड़े संगठनकर्ता होते हैं। कभी-कभी तो वे घोषित तौर पर संगठनकर्ता की भूमिका में उतर आते हैं। वर्तमान मामले में भी यही हुआ था। क्रांतिकारी छात्र-युवा संगठनों को मध्यम वर्ग की इस सद्यः प्राप्त सक्रियता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां बात इस मामले में पूँजीपति वर्ग के रुख पर केन्द्रित है। यह ध्यान देने की बात है कि एक लम्बे समय से इंडिया गेट पर मजदूरों-किसानों की रैलियां प्रतिबंधित हैं। 1990 तक दिल्ली में जुलूस प्रदर्शन का यही स्थल होता था। लेकिन इसके बाद यहां इस पर रोक लगा दी गयी। अब दिल्ली में बड़े विरोध



उदारिकरण के इस दौर में पूँजीपति वर्ग मध्यमवर्ग को अपने पीछे लगाने की हर चन्द कोशिश कर रहा है, खासकर ऊपरी हिस्से को। इसमें वह कामयाब भी है। इसीलिये वह उसे इंडिया गेट पर प्रदर्शन की अनुमति देता है पर मजदूरों व गरीब किसानों को नहीं। लेकिन जब इसी पूँजीपति वर्ग की करतूतों तथा पूँजीवादी व्यवस्था के परिणामों के कारण मध्यम वर्ग उद्वेलित होता है तो पूँजीपति वर्ग उसके साथ तभी तक नरमी से पेश आता है जब तक उसे लगता है कि वह 'शांति-व्यवस्था' कायम रखेगा। तब अन्ना के आंदोलन में या तो पुलिस गायब हो जाती है या फिर खुद को निरस्त कर लेती है। लेकिन जब मध्यम वर्ग छात्र-युवा थोड़ा सा भी अलग व्यवहार करते हैं तो पूँजीपति वर्ग अपना बनैला चेहरा पेश कर देता है। मखमली दस्तानों में छिपाये गये नुकीले पंजे सामने आ जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पूँजीवादी संचार माध्यमों की सरकार को यही सलाह है कि इस पंजे को थोड़ा सभालकर इस्तेमाल करो। ऐसा न हो कि मध्यम वर्ग बिदकने लगे।

प्रदर्शन के लिये रामलीला मैदान तथा मुकर्रर किये गये हैं। इंडिया गेट का मैदान छोटे विरोध प्रदर्शनों के लिये जंतर-मंतर अब दिल्लीवासियों के लिये घूमने-फिरने

की जगह है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार यहां मध्यमवर्गीय प्रदर्शनों के लिये छूट देती रही है। भिन्न-भिन्न मुद्दों पर यहां 'मार्च' और 'मोमबत्ती जुलूस' आयोजित होते रहे हैं।

पिछले साल के अन्ना आंदोलन में यहां अक्सर ही जुलूस और प्रदर्शन आयोजित हुए। सरकार न केवल इनकी इजाजत देती रही है बल्कि यह मानकर चलती रही है कि इससे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन 22-23 दिसम्बर को उसका यह मानना गलत साबित हुआ। इन दिनों में मध्यमवर्गीय छात्र-युवाओं का आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने तय सीमाएं तोड़कर राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा आंसू गैस के गोले छोड़े। 23 तारीख को यह और बड़े पैमाने पर हुआ। इस पूरी घटना में दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हुए। पुलिस ने जहां अपने दमन को जायज ठहराने के लिये विरोध प्रदर्शन में उपद्रवी तत्वों के होने की बात की वहीं विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने के लिये पुलिस कार्रवाई की निंदा की। वे इस बात को सफाई से गायब कर गये कि उनकी सरकार भी ठीक ऐसा ही व्यवहार करती है। इस सिलसिले में भारत के एकाधिकारी पूँजीपति वर्ग के अखबार टाइम्स आफ इंडिया की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। इसने 25 दिसम्बर को लिखा कि इंडिया गेट पर इकट्ठा भीड़ राजनीतिक पार्टियों द्वारा किराये पर जुटाई गई भीड़ नहीं थी इसलिये पुलिस को उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिये था जैसा वह इस तरह की किराये की भीड़ के साथ करती है।

राजनीतिक पार्टियों द्वारा जुटाई गयी किराये की भीड़ से क्या आशय है? इसका आशय है मजदूर और गरीब किसान। केवल ये ही लोग किराये पर जुटाये जा सकते हैं। यहां तक कि मध्यम और धनी किसान भी अपने हित में अपने पैसे से जुटते हैं। ये तो केवल जाहिल मजदूर

और गरीब किसान है जिन्हें थोड़े से लालच से राजनीति पार्टियां इकट्ठा कर सकती हैं और अपने हित साध सकती हैं। ऐसी जाहिल भीड़ को इंडिया गेट पर तो आने ही नहीं देना चाहिए। यदि वह दिल्ली आना चाहे तो उसे रामलीला मैदान में रोकना चाहिए और उसे लाठी-डंडों से नियंत्रित करना चाहिए। वह है ही इसी लायक। यह याद रखने की बात है कि पिछले साल अन्ना आंदोलन के समय पूँजीवादी प्रचार माध्यमों द्वारा यह बात बार-बार कही गयी थी कि रामलीला मैदान में या इंडिया गेट पर जुटनेवाली भीड़ किराये की भीड़ नहीं है। यानी तब भी मजदूर और गरीब किसान जनता के प्रति इसी घृणा को प्रकट किया गया था। एक अन्य संदर्भ में फिर उसी घृणा को प्रकट किया जा रहा है।

उदारिकरण के इस दौर में पूँजीपति वर्ग मध्यमवर्ग को अपने पीछे लगाने की हर चन्द कोशिश कर रहा है, खासकर ऊपरी हिस्से को। इसमें वह कामयाब भी है। इसीलिये वह उसे इंडिया गेट पर प्रदर्शन की अनुमति देता है पर मजदूरों व गरीब किसानों को नहीं। लेकिन जब इसी पूँजीपति वर्ग की करतूतों तथा पूँजीवादी व्यवस्था के परिणामों के कारण मध्यम वर्ग उद्वेलित होता है तो पूँजीपति वर्ग उसके साथ तभी तक नरमी से पेश आता है जब तक उसे लगता है कि वह 'शांति-व्यवस्था' कायम रखेगा। तब अन्ना के आंदोलन में या तो पुलिस गायब हो जाती है या फिर खुद को निरस्त कर लेती है। लेकिन जब मध्यम वर्ग छात्र-युवा थोड़ा सा भी अलग व्यवहार करते हैं तो पूँजीपति वर्ग अपना बनैला चेहरा पेश कर देता है। मखमली दस्तानों में छिपाये गये नुकीले पंजे सामने आ जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पूँजीवादी संचार माध्यमों की सरकार को यही सलाह है कि इस पंजे को थोड़ा सभालकर इस्तेमाल करो। ऐसा न हो कि मध्यम वर्ग बिदकने लगे।

-नागरिक

जैसी करणी वैसी भरणी

भा रत में पूँजीपतियों व मजदूरों के बीच संघर्ष लगातार तीखा होता चला जा रहा है। असम के तिनसुकिया जिले में कुनपाधार चाय बागान के मालिक मृदुल कुमार भट्टाचार्य व उसकी पत्नी को मजदूरों द्वारा उनके घर में ज़िंदा जलाया जाना इसी बात को सामने लाता है। इससे पहले उड़ीसा, नोयडा में ग्रेजियानो, गुडगांव में मारुति-सुजुकी आदि में मजदूरों के संघर्षों में मैनेजमेंट के लोग मारे जा चुके हैं।

यह घटना 26 दिसम्बर को शाम साढ़े चार बजे हुयी। इससे पहले मालिक ने दो दिन पहले 10 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया था और उनको क्वार्टर खाली करने के आदेश दे दिये थे। इससे आक्रोशित होकर 700 मजदूर मालिक के घर पहुंच गये तथा घर को आग लगा दी। जिसमें मालिक व उसकी पत्नी जल कर मर गये।

मृदुल कुमार भट्टाचार्य का पहले भी मजदूरों के साथ संघर्ष होता रहा है। मार्च 2010 में जब इसने एक महिला को छेड़ा तो विरोध करने आई भीड़ पर इसने गोली चलाकर एक स्कूली छात्र की हत्या कर दी और चार अन्य को घायल कर दिया



संघर्ष की राह पर चाय बागान मजदूर

था। उस समय भीड़ ने आक्रोशित होकर आग लगा दी थी। पुलिस व स्थानीय इसके रानी चाय बागान वाली फैक्टरी को प्रशासन ने भट्टाचार्य का ही साथ दिया

मजदूरों का नहीं। यह घटना मजदूरों के दिलों में वर्षों से दबी पड़ी आग को दिखलाती है। आज यह आग उनके दिलों से निकलकर मालिक या मैनेजमेंट के लोगों को जला रही है। चाय बागान में तो मजदूरों का शोषण भी अत्यधिक है। उनको 100 रुपये के लगभग मजदूरी दी जाती है। और पानी के व्यवस्था न होने के कारण अनेक मजदूरों की मौत डायरिया के कारण पिछले दिनों हुई है।

यह घटना पूँजीपति वर्ग को सावधान करती है कि यदि वे मजदूरों के साथ अत्याचार करते चले गये तो उनके घर भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। उनको उस परिणाम को भुगतना पड़ेगा जो उसके कुकर्मों की उपज है। असम की घटना में तो हत्यारा पूँजीपति पूँजीवादी कानूनों का उल्लंघन कर खुलेआम घूम रहा था।

पुलिस उसे जेल में नहीं डाल रही थी। हत्यारे की हत्या पर किसी किस्म की बात की जा सकती है तो यह कि ये उसकी करनी का ही परिणाम है। हां! मजदूरों के आक्रोश की अभिव्यक्ति के अलावा इस तरह की घटना से वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं

होगा। इसके लिये देशभर के मजदूरों को एकजुट होकर आगे आना होगा। अपने नये व इंकलाबी संगठन करने होंगे। उसे पूरे पूँजीपति वर्ग को मात देनी होगी। एक-दो की हत्या से कुछ नहीं होगा।

इस तरह की घटनाएँ हमें यह भी दिखाती हैं कि समाज में मजदूरों के हो रहे भयानक शोषण के बावजूद मौजूदा ट्रेड यूनियन मजदूरों के आर्थिक संघर्षों को लड़ने में भी कितने अक्षम होते जा रहे हैं बावजूद इसके कि आज मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहे हैं। 12-14 घंटे तक काम करना पड़ता है। पी.एफ., ई.एस.आई. की सुविधा छिनती जा रही है।

और ऐसी स्थिति में मजदूर इस तरह के कदम उठा रहे हैं। आज देश के हर मजदूर-मेहनतकश का कार्यभार बनता है कि वे फिर से एक बार क्रांतिकारी संगठन खड़ा करें और अपने आर्थिक लड़ाइयों को लड़ते हुए मजदूर राज को अपना लक्ष्य बनायें। उससे कम पर आर्थिक सुधार ऐसे ही छीन लिए जायेंगे जैसे आज छीने जा रहे हैं।

- 'नागरिक'